



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245]

No. 245]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 16, 2004/आश्विन 24, 1926

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 16, 2004/ASVINA 24, 1926

लघु उद्योग मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2004

विषय :—असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु एक राष्ट्रीय आयोग का गठन।

सं. 5(2)/2004-आई.सी.सी.—संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु एक राष्ट्रीय आयोग बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, तदनुसार सरकार ने असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का फैसला किया है जो कि असंगठित क्षेत्र के लिए एक सलाहकारी निकाय और निगरानीकर्ता की भूमिका निभाएगी। आयोग वैसे उपायों के संबंध में सिफारिश करेगी जो कि इन उपक्रमों में उत्पादकता बढ़ाने हेतु, सतत आधार पर बड़े स्तर पर रोजगारों का सृजन करने के लिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तथा वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में इस क्षेत्र की प्रतियोगितात्मकता बढ़ाने के लिए, ऋण, कच्ची सामग्री, आधार संरचना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन जैसे संस्थागत ढांचे से इस क्षेत्र का संबंध जोड़ने के लिए तथा कुशलता उन्नयन के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं बनाने के लिए आवश्यक होगा।

2. आयोग का संगठन निम्न प्रकार से होगा :

- | | |
|----------------------|--|
| डा. अर्जुन सेनगुप्ता | — अध्यक्ष, जो कि कैबिनेट मंत्री स्तर के होंगे। |
| डा. के. जयशंकर, | — भारत सरकार के सचिव के स्तर के पूर्णकालिक सदस्य |
| पूर्व उप कुलपति, | |
| वारंगल विश्वविद्यालय | |

अन्य पूर्णकालिक सदस्य तथा भारत सरकार के सचिव के स्तर के सदस्य सचिव बाद में नियुक्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, कुछ अंशकालिक सदस्य बाद में शामिल किए जाएंगे।

3. आयोग के विचारार्थ विषय निम्न होंगे :

- (i) उद्यमों की प्रकृति, उनके आकार, विस्तार और कार्यक्षेत्र, तथा रोजगार की मात्रा सहित भारत में असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र की प्रास्थिति की पुनरीक्षा ;
- (ii) उद्यम चलाने में स्वतंत्रता, कच्ची सामग्री तक पहुंच, वित्त, कुशलता, उद्यमिता विकसित, आधार संरचना, प्रौद्योगिकी तथा बाजार के संदर्भ में सामना किए जाने वाले अवरोधों की पहचान तथा उन तक पहुंच आसान बनाने के लिए संस्थागत सहायता तथा सम्पर्क उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षित उपायों का सुझाव देना;
- (iii) विधिक और नीतिगत वातावरण का सुझाव देना जो कि अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र के लिए वृद्धि, रोजगार निर्यात और संवर्धन को नियंत्रित करें।
- (iv) अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन से संबंधित चालू कार्यक्रमों की जांच करना तथा उन्हें पुनःतैयार करने के लिए सुधारों की सिफारिश करना;
- (v) अनौपचारिक क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नवीन कानूनी और वित्तीय लिखतों की पहचान करना;
- (vi) अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार और बेरोजगारी का आकलन करने के लिए वर्तमान व्यवस्थाओं की पुनरीक्षा करना, तथा 1990 के दशक में वृद्धि-दर में स्थिरता के कारणों की जांच करना;
- (vii) अनौपचारिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक रोजगार रणनीति के आवश्यक तत्वों के संबंध में सिफारिश करना।
- (viii) श्रम अधिकारों तथा उद्योग तथा सेवाओं की वृद्धि संबंधी आवश्यकताओं, विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र में, तथा उत्पादकता और प्रतियोगितात्मकता बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए भारतीय श्रम कानूनों की पुनरीक्षा।
- (ix) अनौपचारिक क्षेत्र में श्रम के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा तंत्र की पुनरीक्षा करना तथा उनका आधार-क्षेत्र बढ़ाना।

4. आयोग स्वयं अपनी प्रक्रियाएं निर्धारित करेगा तथा वैसे अधिकारियों से संपर्क करेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे। यह शोध अध्ययन का नाम सुपुर्द कर सकता है जो भी वह समय-समय पर आवश्यक समझे। यह इस प्रकार की सूचनाएं मंगवा सकता है तथा

गवाही ले सकता है जो यह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय /विभाग तथा राज्य/संघ शासित प्रदेश इस प्रकार की सूचना, कागजात तथा अन्य सहायता प्रदान करेंगे जो कि आयोग द्वारा अपेक्षित होगा।

5. आयोग का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। आयोग सरकार को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

स्तुति कक्कड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES RESOLUTION

New Delhi, the 20th September, 2004

Subject.—Constitution of a National Commission on Enterprises in the Unorganised/Informal Sector

No. 5(2)/2004-ICC.—United Progressive Alliance Government had committed in its Common Minimum Programme to set up a National Commission on Enterprises in the Unorganized/Informal Sector, accordingly the Government has decided to set up the National Commission on Enterprises in the Unorganized/Informal Sector as an advisory body and a watchdog for the informal sector. The Commission will recommend measures considered necessary for bringing about improvement in the productivity of these enterprises, generation of large scale employment opportunities on a sustainable basis, particularly in the rural areas, enhancing the competitiveness of the sector in the emerging global environment, linkage of the sector with institutional framework in areas such as credit, raw material, infrastructure, technology upgradation, marketing and formulation of suitable arrangements for skill development.

2. The Commission will have the following composition :

Dr. Arjun Sengupta	-	Chairman in the rank of Cabinet Minister.
Dr. K. Jaishankar, Former Vice Chancellor, Warangal University	-	Full time Member in the rank of Secretary to the Government of India.

Another full time Member and a Member Secretary in the rank of Secretary to the Government of India will be appointed later. In addition, some part time members would be included later on.

3. The terms of reference of the Commission will be as follows :

- (i) Review of the status of unorganized/informal sector in India including the nature of enterprises, their size, spread and scope, and magnitude of employment;
- (ii) Identify constraints faced by small enterprises with regard to freedom of carrying out the enterprise, access to raw materials, finance, skills, entrepreneurship development, infrastructure, technology and markets and suggest measures to provide institutional support and linkages to facilitate easy access to them;
- (iii) Suggest the legal and policy environment that should govern the informal/unorganized sector for growth, employment, exports and promotion;
- (iv) Examine the range of existing programmes that relate to employment generation in the informal/unorganized sector and suggest improvement for their redesign;
- (v) Identify innovative legal and financing instruments to promote the growth of the informal sector;
- (vi) Review the existing arrangements for estimating employment and unemployment in the informal sector, and examine why the rate of growth in employment has stagnated in the 1990s;
- (vii) Suggest elements of an employment strategy focussing on the informal sector;
- (viii) Review Indian labour laws, consistent with labour rights, and with the requirements of expanding growth of industry and services,

particularly in the informal sector, and improving productivity and competitiveness; and

- (ix) Review the social security system available for labour in the informal sector, and make recommendations for expanding their coverage.

4. The Commission will devise its own procedures and may consult such officers as it may consider necessary. It may commission studies as may be required from time to time. It may also call for such information and take such evidence as it may consider necessary. The Ministries/Departments of the Government of India and of States/UTs will furnish such information, documents and other assistance as may be required by the Commission.

5. The term of the Commission will be for a period of one year. The Commission will submit periodic reports to the Government.

STUTI KACKER, Jt. Secy.

31.05.87/2004-2